

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1683
13.12.2023 को उत्तर देने के लिए

एमपीएल-एडी योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य

1683. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी) के तहत स्वीकृत और पूर्ण कार्यों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनेक कार्य अधूरे पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो देरी के क्या कारण हैं और लंबित कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत स्वीकृत और पूर्ण कार्यों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। (अनुबंध -I)

(ख) से (ग) क्षेत्र में एमपीलैड्स का कार्यान्वयन राज्य सरकार के तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय नियमों के अनुसार जिला प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.2.4, पैरा 3.2.12 और पैरा 10.6.1 के अंतर्गत परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रावधान है।

विगत वित्तीय वर्ष तक राज्यवार लंबित कार्यों का विवरण दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (अनुबंध -II)

(घ) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय कार्यों को समय पर पूरा करने और निधि के उपयोग पर जोर देने के लिए राज्य सरकार के साथ नियमित पत्राचार के अलावा वार्षिक समीक्षा बैठक भी आयोजित करता है। जहां भी कार्यों के कार्यान्वयन में देरी, दिशानिर्देशों का उल्लंघन आदि देखा जाता है, तो राज्य सरकार/जिला प्राधिकारी को उचित कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।

अनुबंध- I

{दिनांक 13.12.2023 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1683 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुबंध }

तालिका: स्वीकृत और पूरे किए गए कार्यों का विवरण

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूरे किये गये कार्यों की संख्या
1	2018-19	127740	105167
2	2019-20	53365	62236
3	2020-21	47221	54101
4	2021-22	28366	39778
5	2022-23	44976	40451

नोट-: 1. स्वीकृत कार्यों की संख्या और पूरे किये गये कार्यों की संख्या में क्रमशः पिछले वर्ष के अनुशंसित और स्वीकृत कार्य भी शामिल हैं।

2 एमपीलैड्स पोर्टल पर डेटा नोडल जिला प्राधिकारियों द्वारा संसूचित हैं।

{दिनांक 13.12.2023 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1683 के उत्तर के भाग (ख) से (ग) में संदर्भित अनुबंध }

तालिका: राज्यवार लंबित कार्यों का विवरण

क्र.सं	राज्य	लंबित कार्यों की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	45
2	आंध्र प्रदेश	20264
3	अरुणाचल प्रदेश	82
4	असम	6864
5	बिहार	11541
6	चंडीगढ़	108
7	छत्तीसगढ़	3715
8	दादर और नागर हवेली	44
9	दमन और दीव	134
10	दिल्ली	686
11	गोवा	219
12	गुजरात	13117
13	हरियाणा	3481
14	हिमाचल प्रदेश	13293
15	जम्मू और कश्मीर	4565
16	झारखंड	4919
17	कर्नाटक	12818
18	केरल	3529
19	लक्षद्वीप	23
20	मध्य प्रदेश	13969
21	महाराष्ट्र	16680
22	मणिपुर	869
23	मेघालय	454
24	मिजोरम	139
25	नागालैंड	25
26	मनोनीत	1550
27	ओडिशा	10807
28	पुदुचेरी	76
29	पंजाब	7529
30	राजस्थान	8789
31	सिक्किम	84
32	तमिलनाडु	4982
33	तेलंगाना	4138

34	त्रिपुरा	122
35	उत्तर प्रदेश	21231
36	उत्तराखंड	4256
37	पश्चिम बंगाल	9203

नोट:- एमपीलैड्स पोर्टल पर डेटा नोडल जिला प्राधिकारियों द्वारा संसूचित हैं।
